

कांग्रेस-सपा लोगों को वोट का गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं : डॉ. यादव

भोपाल (काप्र)।

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने उत्तरप्रदेश के श्रावस्ती लोकसभा की गैसडी विधानसभा के पचपेड़वा में भाजपा प्रत्याशी साकेत मिश्रा के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस और समाजवादी विचारधारा के लोग कुछ लोगों को अपने वोटों का गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं। इनकी मानसिकता ही ऐसी है। पहले अंग्रेजों ने यह काम किया था। अंग्रेजों ने 'फूट डालो शासन करो' की नीति से देश के हिन्दू-मुसलमानों को हमेशा लड़ाया और अब यह काम कांग्रेस पार्टी भी कर



रही है। कांग्रेस वह पुंछ है, जो सीधी नहीं हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं भाजपा सरकारों ने हर वर्ग, हर क्षेत्र के लोगों को सम्मान दिया, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी वर्ग विशेष को ही मानते हैं। मुस्लिम देशों में सबसे ज्यादा सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो रहा है। भाजपा हर वर्ग को सम्मान देती है, लेकिन कांग्रेसी, समाजवादियों के पेट में दर्द होता है। कांग्रेस हमेशा से सिर्फ वोट बैंक की राजनीति ही करती रही है। मुस्लिम भाई-बहनों के कांग्रेस ने सिर्फ वोट लिए हैं, उनके विकास के लिए कुछ नहीं किया। कांग्रेस के अंदर अंग्रेजों के लक्षण समाहित हैं। जब अंग्रेजों ने भारत में राज किया तो उन्होंने हमेशा फूट डालो शासन करो की नीति अपनाई। इसके बाद जब अंग्रेज चले गए तो यह काम

कांग्रेसियों ने भी शुरू कर दिया। कांग्रेस भी अंग्रेजों के सिद्धांतों पर चलते हुए फूट डालो शासन करो की नीति से सरकार चलाती रही। हमेशा से देश के अंदर हिन्दू-मुसलमानों के बीच में फूट डालकर शासन करती रही, लेकिन अब इस देश की जनता समझदार हो गई है और अब वह कांग्रेस की रग-रग को जानने लगी है। डॉ. यादव ने कहा है कि हम जब भी हमारे देवी-देवताओं के जयकारे लगाते हैं तो सबसे ज्यादा दिक्कतें, परेशानियां कांग्रेसियों को होती है। उन्हें हमारे देवी-देवता पसंद नहीं है। कांग्रेस की मानसिकता ही विरोध करने की रही है। आज जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे ज्यादा मान-सम्मान मुस्लिम देशों में मिल रहा है तो वहीं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रक्षाबंधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए

राखी भेज रही हैं। प्रधानमंत्री भी उनके लिए साड़ी भेजते हैं। अब कांग्रेसी कह रहे हैं कि यदि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए तो वे संविधान को ही बदल डालेंगे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता है कि प्रधानमंत्री श्री मोदी 10 वर्षों से देश के प्रधानमंत्री हैं। कांग्रेस संविधान के नाम पर देशवासियों के बीच में भ्रम फैला रही है। **एक पार्टी का नाम बदलना चाहिए:** मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आमजन की पार्टी है। हमारे यहां जनता से ही प्रधानमंत्री बनता है, मुख्यमंत्री बनता है, मंत्री, सांसद, विधायक बनता है, लेकिन एक पार्टी ऐसी भी है, जिसमें एक ही परिवार से प्रधानमंत्री, अध्यक्ष बनता है। इस पार्टी का नाम बदलना चाहिए।

बचपन में मोटापे व उच्च रक्तचाप के चिंताजनक रुझान

भोपाल (काप्र)।

विश्व उच्च रक्तचाप दिवस के उपलक्ष्य में एम्स ने बचपन में मोटापे की गंभीर समस्या और उच्च रक्तचाप से इसके खतरनाक संबंध पर प्रकाश डाला। इस वर्ष की थीम, अपने रक्तचाप को सटीक रूप से मापें, इसे नियंत्रित करें, लंबे समय तक जीवित रहें! दीर्घायु और स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए सटीक रक्तचाप की निगरानी और नियंत्रण की आवश्यकता पर जोर देता है।

परंपरागत रूप से एक वयस्क बीमारी मानी जाने वाली उच्च रक्तचाप अब बच्चों में भी तेजी से फैल रही है, जो बड़े पैमाने पर बचपन के मोटापे में वैश्विक वृद्धि के कारण है। दीर्घकालिक हृदय संबंधी जोखिमों को कम करने के लिए इसकी शीघ्र पहचान और हस्तक्षेप की तत्काल आवश्यकता महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में एम्स भोपाल द्वारा 60 मोटे बच्चों को शामिल करते हुए किए गए एक महत्वपूर्ण अध्ययन में रक्तचाप की निगरानी के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण का उपयोग किया गया, जिसमें कार्यालय-आधारित माप, एंबुलेटरी रक्तचाप की निगरानी (एबीपीएम), और घरेलू रक्तचाप की निगरानी (एचबीपीएम) शामिल है। अध्ययन के निष्कर्ष चौंकाने वाले और

चिंताजनक दोनों हैं।

अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष

उच्च रक्तचाप की व्यापकता 43.3प्रतिशत मोटे बच्चों का निदान 24-घंटे एबीपीएम का उपयोग करके किया गया, जो उच्च रक्तचाप के निदान के लिए स्वर्ण मानक है। इसमें विशेष रूप से, 22ब को छिपा हुआ उच्च रक्तचाप था, जिसका पता केवल 24-घंटे एबीपीएम के माध्यम से लगाया जा सकता था।

एम्स द्वारा 60 मोटे बच्चों

पर किए गए अध्ययन

के निष्कर्ष

घर बनाम कार्यालय रक्तचाप की निगरानी: जबकि घर के रक्तचाप की निगरानी कार्यालय माप की तुलना में अधिक सटीक है, लेकिन यह 24 घंटे के एबीपीएम की तुलना में कम संवेदनशील है। एबीपीएम की बेहतर सटीकता के बावजूद, बाल चिकित्सा देखभाल में इसका कम उपयोग किया जाता है।

अंत-अंग क्षति: चिंताजनक रूप से, 25 प्रतिशत बच्चों में अंत-अंग क्षति के लक्षण दिखाई दिए, विशेष रूप से बाएं वेंट्रिकुलर द्रव्यमान सूचकांक में वृद्धि, जो लंबे समय

तक उच्च रक्तचाप का संकेत देती है। एम्स के कार्यपालक निदेशक प्रो. अजय सिंह ने रक्तचाप की शीघ्र जांच की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर जोर दिया। बच्चों का उच्च रक्तचाप के लिए मूल्यांकन किया जाना चाहिए, और स्कूल इन जांचों के लिए आदर्श स्थान हैं। सामान्य चिकित्सकों और बाल रोग विशेषज्ञों के बीच जागरूकता बढ़ाना आवश्यक है। समय पर हस्तक्षेप और बच्चों में हृदय रोग के भविष्य के बोझ को कम करने के लिए सटीक निगरानी के माध्यम से प्रारंभिक पता लगाना महत्वपूर्ण है। एम्स में बाल चिकित्सा नेफ्रोलॉजी और उच्च रक्तचाप विभाग के प्रो. गिरीश सी. भट्ट ने जेएएमए बाल रोग विज्ञान में प्रकाशित एक हालिया कनाडाई अध्ययन का संदर्भ दिया, जिसमें कहा गया है कि उच्च रक्तचाप से पीड़ित युवाओं को वयस्कता में गंभीर हृदय संबंधी जोखिम का 2 से 3 गुना अधिक खतरा होता है। बाद के जीवन में हृदय संबंधी रुग्णता और मृत्यु दर को कम करने के लिए बचपन में प्रारंभिक पहचान और निवारक रणनीतियाँ आवश्यक हैं। डॉ. अथिरा पी को यह पोस्टडॉक्टोरल थीसिस एक सहयोगात्मक प्रयास के रूप में अमेरिकन जर्नल ऑफ हाइपरटेंशन में प्रकाशित हुई है। योगदान देने वाले लेखकों में डॉ. अंबर कुमार, डॉ. महेश माहेश्वरी, डॉ. अभिजीत पी. पखारे, डॉ. शिखा मलिक और डॉ. रूपेश रैना शामिल हैं।

कटनी की कई इंडस्ट्रीज पर आईटी के छापे से हड़कंप

भोपाल (काप्र)।कटनी जिले के कई बड़े व्यापारियों के घर और उनके कई ठिकानों पर एक साथ 50 से ज्यादा लगजरी कारों के साथ इनकम टैक्स के 100 से ज्यादा अधिकारियों की टीम ने छापेमार कार्रवाई की है।

ये सभी व्यापारी दाल मिल, चावल मिल और कई बड़े व्यापार करते हैं जिसमें से एक सबसे बड़ा व्यापार करने वाले अनिल इंडस्ट्रीज के तीन भाइयों के घर व उनके ठिकानों पर कार्रवाई की गई इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों ने सुबह सभी जगहों पर दबिश देते हुए कागजातों को खंगाल रही है। माधवनगर की प्रतिष्ठित फर्म अनिल इंडस्ट्रीज के अलावा कई बड़े व्यापारियों के ठिकानों व उनके घरों पर सुबह ही इनकम टैक्स दबिश दी है। अधिकारियों की टीम मिल सहित अनिल के निरंकारी भवन के सामने स्थित बंगला में भी जांच कर रही है।

करीब 50 से ज्यादा लगजरी कारों से जबलपुर, भोपाल के अधिकारियों के दल ने एक साथ यह दबिश दी। सुबह से ही दस्तावेजों को खंगालने के लिये जांच शुरू कर दी। **अनिल इंडस्ट्रीज पर अरबों की कर चोरी का आरोप:** कार्रवाई के दौरान इनकम टैक्स दल के साथ पुलिस टीम भी मौजूद है। बताया जाता है कि अनिल इंडस्ट्रीज उद्योग जिले का एक उभरता नाम है। विगत कई दिनों से यह इनकम टैक्स के निशाने पर था। अनिल इंडस्ट्रीज और कई बड़े व्यापारियों पर अरबों रुपए के कर चोरी की आशंका व्यक्त की जा रही है। जांच कहां तक पहुंची और टीम को क्या-क्या हाथ लगा है इसकी अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है करीब दो दिन तक जांच चलने का अनुमान लगाया जा रहा है।

ईपीएफओ के कर्मचारी को घूस लेते सीबीआई ने दबोचा

भोपाल। सीबीआई टीम ने

क्षेत्रीय ईपीएफओ कार्यालय ग्वालियर के सामाजिक सुरक्षा सहायक को घूस लेते हुए रोहो हाथों गिरफ्तार किया है। सीबीआई को फरियादी ने शिकायत करते हुए बताया था, कि उसके पक्ष में पेंशन जारी करने के लिये आरोपी द्वारा उससे 25 हजार की रिश्त की माँग की जा रही है। इतना ही नहीं आरोपी ने रिश्त की पहली किस्त के रुप में अपने बैंक खाते में फरियादी से 10 हजार की रकम जमा भी करवा ली थी। शिकायत की जाँच के बाद सीबीआई ने आरोपी एसएएफ, क्षेत्रीय ईपीएफओ कार्यालय ग्वालियर के खिलाफ 15 मई को मामला दर्ज किया था। इसके बाद जब आरोपी ने शिकायतकर्ता से 10 हजार की रिश्त और ली तब सीबीआई ने सामाजिक सुरक्षा सहायक को गिरफ्तार कर लिया।

जिला बैंक के कोर मास्टर ट्रेनर्स के पांच दिवसीय प्रशिक्षण का समापन

भोपाल (काप्र)।

अपेक्स बैंक ट्रेनिंग कॉलेज एवं नाबाई के संयुक्त तत्वाधान में जिला बैंक के कोर मास्टर ट्रेनर्स के 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन आज शुक्रवार को अपेक्स बैंक ट्रेनिंग कॉलेज की प्राचार्य एवं संयुक्त आयुक्त, सहकारिता श्रीमती अरुणा दुबे एवं नाबाई के महाप्रबंधक कमर जावेद, उपमहाप्रबंधक नन्दू जे. नाइक ने किया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में सभी उपस्थित प्रशिक्षणार्थियों से समूह चर्चा एवं फीडबैक के आधार पर इन्टलेक्ट से उपस्थित ट्रेनर्स जितेन्द्र मांझी, त्रिलोचन सिंह, मनोज कुमार, अभिषेक, लीला नान्द, रमेश रेड्डी, जितेन्द्र जोशी, चन्द्र प्रकाश द्वारा प्रदेश के 38 जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों के 129 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित किया गया एवं उनके द्वारा कार्य-



व्यवहार के दौरान आने वाली व्यवहारिक कठिनाईयों एवं समस्याओं का निवारण भी किया। श्रीमती दुबे के द्वारा इन्टलेक्ट टीम के 08 सदस्यों एवं अतिथियों को मोमेंटो भेंट कर सम्मानित किया गया। अपेक्स बैंक के प्रबंधक आई. टी. आशीष राजोरिया, संकाय सदस्य आर. के. चौरागढ़ी के साथ वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित हुए। कार्यक्रम का संचालन अरविंद बौद्ध ने किया। उल्लेखनीय है कि उक्त पांच दिवसीय पैक्स कम्प्यूटराईजेशन प्रशिक्षण

कार्यक्रम का शुभारंभ अपेक्स बैंक के प्रबंध संचालक मनोज गुप्ता एवं श्री जावेद ने किया था। श्री गुप्ता ने अवगत कराया कि प्रदेश की 1001 पैक्स लाइव हो गई है और अति शीघ्र ही हम इस क्षेत्र में प्रगति हेतु प्रयासरत है। श्री गुप्ता ने कुशल मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए बैंक की प्रशासक एवं प्रमुख सचिव सहकारिता श्रीमती दीपाली रस्तोगी एवं आयुक्त सहकारिता मनोज सरयाम का धन्यवाद ज्ञापित किया तथा अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई दी।

विद्यार्थी विज्ञान मंथन का दो दिवसीय नेशनल कैंप आज से

भोपाल (काप्र)। विज्ञान भारती द्वारा 18-19 मई को

विद्यार्थी विज्ञान मंथन का दो दिवसीय नेशनल कैंप का आयोजन आइसर में होने जा रहा है। संपूर्ण भारत के 36 प्रान्तों से 486 विद्यार्थी, शिक्षक, विज्ञान चिंतक, वैज्ञानिक, वैज्ञानिक संचारक सहित कुल 1000 व्यक्ति इस प्रतियोगिता सह कार्यशाला मे भाग ले रहे हैं।

विद्यार्थी विज्ञान मंथन भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के सहयोग से विज्ञान भारती की एक पहल है। वीवीएम छठी से ग्यारहवीं कक्षा के स्कूली छात्रों के बीच विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है, जिसकी परिकल्पना छात्र समुदाय में वैज्ञानिक प्रतिभा की पहचान करने के लिए की गई है। इसके उद्देश्य विद्यार्थियों में शुद्ध विज्ञान के प्रति रुचि पैदा करना, कार्यशालाओं और अन्य आयोजनों के माध्यम से छात्रों को व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करना, छात्रों को विज्ञान के क्षेत्र में अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए तैयार करने हेतु मार्गदर्शक प्रदान करना, वैज्ञानिक सोच रखने वाले छात्रों की पहचान करने के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित करना, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर सफल विद्यार्थियों की पहचान कर उन्हें सम्मानित करना, विजेताओं के लिए देश के विभिन्न अनुसंधान एवं विकास संस्थानों में एक्सपोजर विजिट आयोजित करना है। राष्ट्रीय स्तर पर चयनित विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप 2000 रूपया प्रतिमाह तथा 1 वर्ष के लिए राष्ट्रीय संस्थान में 1 से 3 सप्ताह का भ्रमण निः शुल्क कराया जाता है। दो दिवसीय इस कार्यशाला में भारतभर से वैज्ञानिक एवं नवाचारी जुड़ेंगे।

मतगणना अभिकर्ता को केलकुलेटर की अनुमति देने की मांग

भोपाल (काप्र)। मप्र में लोकसभा के चुनाव हेतु मतदान सम्पन्न हो चुका है। देश भर में लोकसभा चुनाव की मतगणना 4 जून को होना नियत है। मतगणना स्थल पर मतों की गणना मौखिक रूप से किया जाना वर्तमान परिवेश में अत्यधिक कठिन कार्य है। चुनाव ड्यूटी में अधिकारियों-कर्मचारियों द्वारा मतगणना को कार्य केलकुलेटर से किया जाता है। प्रदेश कांग्रेस के चुनाव आयोग कार्य प्रभारी जेपी धनोपिया ने चुनाव आयोग से पत्र लिखकर मांग की है कि चुनाव परिणाम के दिन नियुक्त मतगणना अधिकर्ता को भी मतों की गणना हेतु मतगणना स्थल पर केलकुलेटर ले जाने की अनुमति दी जाए। चूँकि मतगणना अधिकर्ता के लिए जारी पुस्तिका में जिन उपकरणों को मतदान स्तर पर ले जाना प्रतिबंधित होना नहीं दर्शाया गया है उसमें केलकुलेटर सम्मिलित नहीं है। श्री धनोपिया ने मांग की है कि मतगणना दिवस 4 जून को मतगणना अधिकर्ता को मतगणना स्थल पर गणना के उपयोग करने हेतु केलकुलेटर ले जाने की अनुमति प्रदान की जाए जिससे कि उन्हें गणना करने में कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े और मतों की गणना आसानी से की जा सके।

स्पेशल खबर भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता और साक्ष्य अधिनियम-2023...

न्याय प्रणाली को अधिक सुलभ, जवाबदेह, भरोसेमंद बनाने के प्रयास : प्रियंका

भोपाल (काप्र)।

भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 अपराधिक न्याय प्रणाली को अधिक सुलभ, जवाबदेह, भरोसेमंद और न्याय प्रेरित बनाने के प्रयास हैं। ये कानून 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होंगे।

बात सुश्री प्रियंका शुक्ला, पुलिस उपायुक्त, भोपाल जोन-1 ने पीआईबी द्वारा इन नए कानूनों पर आयोजित कार्यशाला 'वार्तालाप' को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 में पीड़ितों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कई तरीकों से व्यवस्था की गई है। 30 से अधिक ऐसे प्रावधान हैं जो पीड़ितों के अधिकारों को प्रभावी ढंग से प्राथमिकता देते हुए उनकी रक्षा करते हैं। सुश्री शुक्ला



ने कहा कि पहले चार्जशीट की प्रति सिर्फ आरोपी को दी जाती थी, अब पीड़ित को भी चार्जशीट की कॉपी मिलेगी। उन्होंने कहा कि जांच में वैज्ञानिक तरीकों को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। 7 वर्ष या इससे अधिक की सजा के प्रवाधान वाले सभी अपराधों में फॉरेंसिक अनिवार्य होगा। सुश्री शुक्ला ने कहा कि ये कानून

बेटर जस्टिस डिलेवरी सिस्टम की दिशा में मील के पत्थर साबित होंगे। उन्होंने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की अन्य विशेषताओं पर भी विस्तार से प्रकाश डाला। सुश्री शुक्ला ने संबंधित विषय पर मीडियामर्मियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के भी जवाब दिए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अतिरिक्त जिला

अभियोजन अधिकारी श्रीमती प्रियंका उपाध्याय ने कहा कि तीनों नए कानूनों का मकसद सजा देने की बजाय न्याय देना है। उन्होंने कहा कि इन कानूनों का प्रयास तय समय पर न्याय दिलाना है। श्रीमती उपाध्याय ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता में महिलाओं एवं बच्चों के खिलाफ अपराध पर एक नया अध्याय सामाहित किया गया है। उन्होंने कहा कि इन कानूनों में टेक्नोलॉजी के उपयोग पर ज्यादा बल दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक/डिजिटल साक्ष्य अब साक्ष्य के अन्य रूपों के समान गिने जाएंगे। श्रीमती उपाध्याय ने कहा कि इन कानूनों में पीड़ितों को सशक्त बनाने के लिए बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। पीआईबी के अपर महानिदेशक प्रशांत पाठराबे ने कार्यशाला के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम,

2023 के 25 दिसंबर 2023 को कानून बनने के साथ ही भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में एक नये युग की शुरुआत हुई है। उन्होंने इन कानूनों के अन्य प्रावधानों के बारे में भी चर्चा की। कार्यशाला को संबोधित करते हुए पीआईबी, भोपाल के उप निदेशक डॉ. सत्येन्द्र शरण ने कहा कि नए कानूनों के लागू होने के साथ कोई व्यक्ति ई-एफआईआर या किसी भी पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करा सकता है, भले ही थाने का कार्य क्षेत्र कुछ भी हो। साथ ही, सख्क की प्रति इलेक्ट्रॉनिक तरीके से प्राप्त की जा सकती है। जांच में प्रगति के बारे में पुलिस द्वारा 90 दिनों के भीतर सूचित करना जरूरी होगा। कार्यशाला में शहर के पत्रकारों ने बह-चदकर हिस्सा लिया। पत्रकारों ने संबंधित विषय पर विशेषज्ञों से प्रश्न भी पूछे। विशेषज्ञों ने पत्रकारों के सवालों के बखूबी जवाब दिए।

